जनसत्ता

हताशा के कदम

जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद पाकिस्तान की झुंझलाहट लगातार बढ़ रही है। हालांकि इस मामले को उसने अंतरराष्ट्रीय बिरादरी के सामने भी रखा और मदद की गुहार लगाई, मगर कोई कामयाबी नहीं मिल पाई। जो अमेरिका पहले मध्यस्थता करने की बात कर रहा था, उसने भी कह दिया कि यह दोनों देशों के बीच का मामला है, वे आपस में बैठ कर इसका समाधान निकालें। इस तरह पाकिस्तान हताश है। इसी हताशा में वह कुछ ऐसे कदम उठाने का प्रयास करता है जिससे भारत को सबक सिखाया जा सके, उसे परेशान किया जा सके। मगर अब तक के उसके सारे कदम बेअसर साबित हो चुके हैं। इसी सिलसिले में वह भारत के साथ अपने सारे हवाई मार्ग बंद करने पर विचार कर रहा है। पाकिस्तान के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री फवाद चौधरी ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री यह फैसला जल्दी ही करने वाले हैं। इससे संबंधित कानूनी पहलुओं पर विचार चल रहा है। मगर यह समझ से परे है कि ऐसा करके आखिर पाकिस्तान को हासिल क्या होगा! इससे महज उसकी कुछ खुनस ही मिटेगी।

अगर पाकिस्तान भारत आने-जाने वाले विमानों को अपनी सीमा से होकर नहीं गुजरने देने का फैसला करता है तो निस्संदेह विमानन कंपनियों का खर्चा बढ़ेगा। मगर ऐसा नहीं कि इससे सिर्फ भारत को नुकसान होगा, पाकिस्तान को भी राजस्व घाटा उठाना पड़ेगा। फिर यह पहली बार नहीं होगा, जब पाकिस्तान अपने हवाई मार्ग भारत के लिए बंद कर देगा। बालाकोट पर हवाई हमले के बाद भी उसने ऐसा किया था। इसकी वजह से भारत से उड़ान भरने वाले विमानों को कुछ लंबा रास्ता तय करके दूसरे देशों में पहुंचना पड़ता था। मगर फिर उसने हवाई रास्ते खोल दिए। ऐसे फैसलों से विमानों को थोड़ा अधिक समय उड़ान भरनी पड़ती है, उनका खर्च बढ़ जाता है। जाहिर है, इसका असर मुसाफिरों पर भी पड़ता है। मगर ऐसा कभी नहीं हुआ कि बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द करनी पड़ी हों। इसलिए अगर इस बार भी वह ऐसा फैसला करता है, तो भारतीय या दूसरी विमानन कंपनियों के लिए बहुत घबराने की बात नहीं होगी।

जब दो देशों के बीच तनाव बढ़ता है तो इस तरह के फैसले संभावित होते हैं। पुलवामा के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ कई कारोबारी रिश्ते तोड़ लिए थे। इसी तरह बालाकोट और फिर धारा 370 हटने के बाद पाकिस्तान ने भी कई कारोबारी गतिविधियों पर विराम लगा दिया। अब वह पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान के साथ भारत के व्यापार पर भी अंकुश लगाने पर विचार कर रहा है। वह भारत से अफगानिस्तान के लिए जाने वाली सड़कों को भी बंद करने पर विचार कर रहा है। जाहिर है, इससे वाणिज्यिक वाहनों को थोड़ा लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, जिससे माल ढुलाई का खर्च बढ़ेगा। पर पाकिस्तान को इसका भी नुकसान उठाना पड़ेगा। पहले ही भारत के साथ उसके व्यापारिक रिश्ते खत्म होने से उसे बड़े पैमाने पर घाटा उठाना पड़ रहा है। वहां की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे में खुनस में उठाए गए कदम उसके ही लिए परेशानी का सबब बनेंगे। इमरान खान जिस तरह खुद को पाकिस्तान की तरक्की के लिए समर्पित बताते रहे हैं, उससे लगता रहा है कि वे भारत के साथ रिश्ते बेहतर बनाने के पक्ष में हैं। पर हवाई रास्ते बंद करने और व्यापार रोक देने जैसे कदमों पर उनके विचार करने से यही जाहिर है कि वे बातचीत के जरिए समाधान के पक्ष में नहीं हैं।

हिंसा की जमीन

राजधानी दिल्ली सहित देश के अलग-अलग हिस्सों में मंगलवार को पीट-पीट कर मार डालने की जो दहला देने वाली घटनाएं सामने आईं, उनसे एक बार फिर यह सवाल उठा है कि आखिर लोग इतने असहिष्णु और हिंसक क्यों होते जा रहे हैं। किसी को बच्चा चोर समझ कर, तो किसी को डायन बता कर मार डालने की घटनाएं वाकई चिंताजनक हैं। पुरानी दिल्ली स्टेशन के बाहर मंगलवार को एक मदरसे के शिक्षक को पटरी पर दुकान लगाने वाले कुछ दुकानदारों ने पीट-पीट कर मार डाला। बात सिर्फ इतनी थी कि इस शिक्षक ने हेडफोन उठा कर देखा और पसंद न आने पर खरीदने से इंकार कर दिया। इसी को लेकर विवाद हो गया, जो उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। मुंबई में एक वृद्ध ठेले वाले को कुछ लोगों ने पीट-पीट कर इसलिए मार दिया कि उसने कुछ लोगों को वहां कचरा फेंकने से मना किया था। बिहार के नवादा जिले के एक गांव में एक वृद्ध महिला को डायन बता कर पीट-पीट कर मार डाला गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश के संभल में भीड़ ने बच्चा चोर होने के शक में एक व्यक्ति की हत्या कर दी। ऐसे ही एक मामले में मेरठ में एक महिला को बांध कर पीटा गया। ये सारी घटनाएं बताती हैं कि देश में कैसा खौफनाक भीड़ तंत्र बन चुका है, जिसका कानून-व्यवस्था में न कोई भरोसा है, न ही उसका कोई खौफ।

ऐसी घटनाएं पिछले कुछ सालों में ज्यादा बढ़ी हैं। कभी 'गोरक्षक' कानून-व्यवस्था को हाथ में लेते हैं और 'गोतस्करों' को ठिकाने लगा देते हैं तो कभी बच्चा चोरी के शक में अनजान व्यक्ति भीड़ का शिकार हो जाता है। कई बार ऐसी घटनाएं धर्म-विशेष के लोगों के साथ हुई हैं, जिन्हें 'जय श्रीराम' का नारा लगाने को मजबूर करते हुए पीट-पीट कर मार दिया गया। कुछ घटनाओं को लेकर तो कहा जा सकता है कि इन्हें अंजाम देने वाले किसी न किसी रूप में प्रेरित होकर ऐसा करते होंगे, लेकिन राजधानी दिल्ली में जिस मदरसे के शिक्षक को हेडफोन पर विवाद के कारण मार डाला गया, वह ज्यादा गंभीर चिंता का विषय है। इस घटना को अंजाम देने वालों ने जरा भी नहीं सोचा कि कुछ रुपए की चीज के पीछे वे एक व्यक्ति को जिस तरह मौत के घाट उतार रहे हैं उसका हश्र क्या हो सकता है। इस घटना से हर आदमी के भीतर यह खौफ पैदा होना स्वाभाविक है कि रास्ते चलते न जाने क्या विवाद हो जाए और लोग पीट-पीट कर मार डालें! ऐसी घटनाओं के पीछे सबसे बड़ा कारण ही यही है कि लोगों में कानून-व्यवस्था का भय खत्म हो गया है। शायद वे जानते हैं कि पुलिस कुछ नहीं करेगी। इस घटना में भी पुलिस ने कुछ पटरी दुकानदारों के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया। हैरानी की बात है कि भीड़ भरे बाजार में किसी ने उस शिक्षक को बचाने की कोशिश भी नहीं की।

समाज में बढ़ती इस तरह की हिंसक प्रवृत्ति एक लोकतांत्रिक और सभ्य राष्ट्र के लिए शर्मनाक है। इस तरह की घटनाओं का ग्राफ जिस तेजी से बढ़ रहा है, उससे साफ है कि देश में कानून-व्यवस्था का कोई मतलब नहीं रह गया है। ऐसी घटनाएं पुलिस और समाज दोनों के लिए चुनौती बन गई हैं। ऐसे अपराधियों से निपटने के लिए कानून भी काफी हैं, लेकिन ठप तंत्र में सब बेअसर साबित हो रहे हैं।

कल्पमेधा

अहंकारी हमेशा केवल अपने महान कार्यों का वर्णन करता है और दूसरों के सिर्फ कुकर्मों का।
-स्पिनोजा

मतभेदों में उलझता जी-7

ब्रह्मदीप अलूने

जी-7 समूह के देश दुनिया में पूंजीवाद का प्रतीक हैं और इसमें रूस का होना या न होना भी बड़ा मुद्दा रहा है जो सदस्य देशों के बीच विरोधाभास को बढ़ाता रहा है। इस समूह के देशों की आपसी असहमतियों का आक्रामक कूटनीतिक प्रदर्शन भी चुनौतीपूर्ण रहा है। क्रीमिया पर रूस के आधिपत्य के बाद लोकतांत्रिक मूल्यों के नाम पर वर्ष 2014 में रूस को जिस तरह से समूह से बाहर का रास्ता दिखाया गया था, उसे लेकर भी आपसी मतभेद सामने आते रहे हैं।

वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर विचार और परामर्श के विकसित देशों के सबसे बड़े संगठन जी-7 का फ्रांस में शिखर सम्मेलन ऐसे समय पर आयोजित हुआ जब अमेरिका की रूस से कूटनीतिक तकरार और चीन से आर्थिक तनाव चरम पर है। दुनिया के विकसित और अग्रणी राष्ट्रों के इस समूह में जहां एक ओर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कूटनीतिक और राष्ट्रीय नीतियों को लेकर गहरे मतभेद सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर युद्ध, राष्ट्रवाद, दक्षिणपंथ के उभार, मुक्त बाजार के साथ अप्रवासन का विरोध और परमाणु हथियारों का जखीरा जुटाने की होड़ के बीच शांति और समग्र विकास के प्रति प्रतिबद्धता में गहरा अंतर्द्वंद दिखाई साफ नजर आ रहा है।

दरअसल, अमेरिका, फ्रांस, इटली, कनाडा, जर्मनी, जापान और इंग्लैंड जी-7 के सदस्य राष्ट्र हैं जो स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र और मानवाधिकारों की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का इजहार करते रहे हैं। उच्च आय और विकास के उच्च पैमाने स्थापित करने वाले जी-7 के राष्ट्राध्यक्ष हर साल अलग-अलग देशों में शिखर सम्मेलन आयोजित करते हैं और आर्थिक गतिविधियों के साथ ही जलवायु परिवर्तन, गरीबी, असमानता, सुरक्षा, पर्यावरणीय संकट जैसे सामाजिक सरोकारों और वैश्विक समस्याओं से जुड़े विषयों पर भी विमर्श करते हैं। इन सबके बीच यह भी दिलचस्प है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उभार के बाद महाशक्ति अमेरिका की भूमिका वैश्विक हितों से ज्यादा अमेरिकीवाद पर केंद्रित हो गई है और इसके प्रभाव से जी-7 भी अछूता नहीं है। जी-7 समूह के देश दुनिया में पूंजीवाद का प्रतीक हैं और इसमें रूस का होना या न होना भी बड़ा मुद्दा रहा है जो सदस्य देशों के बीच विरोधाभास को बढ़ाता रहा है। इस समूह के देशों की आपसी असहमतियों का आक्रामक कूटनीतिक प्रदर्शन भी चुनौतीपूर्ण रहा है।

क्रीमिया पर रूस के आधिपत्य के बाद लोकतांत्रिक मूल्यों के नाम पर वर्ष 2014 में रूस को जिस तरह से समूह से बाहर का रास्ता दिखाया गया था, उसे लेकर भी आपसी मतभेद सामने आते रहे हैं। अब ट्रंप ने जी-7 को रूस के बिना अधूरा बताया है, वहीं अन्य देश ट्रंप की नीतियों को लेकर सहज नहीं लग रहे।

जी-7 दुनिया के औद्योगिक देशों का समूह है लेकिन इन देशों में से अधिकतर अपनी बड़ी अर्थव्यवस्था के मुकाबले वैश्विक अर्थव्यवस्था में बहुत कम भागीदारी कर रहे हैं। भारत और चीन की चुनौती इस समूह के सामने बरकरार है। यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा देश जर्मनी है और उसका मुसलिम शरणार्थियों के प्रति उदार रवैया ट्रंप के आक्रामक राष्ट्रवाद के विरोध में नजर आता है। जर्मनी के बड़े राजनेता जिकमार गैबरियल ट्रंप को शांति और समृद्धि के लिए खतरा बता चुके हैं। हाल में ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की आर्थिक नीतियों की कड़ी आलोचना करते हुए आरोप लगाया था कि फ्रांस गूगल जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कर लगाने की तैयारी कर रहा है। ट्रंप प्रशासन ने कहा था कि फ्रांस की ओर से लगाया गया कर अन्यायपूर्ण ढंग से अमेरिकी टैक कंपनियों को नुकसान पहुंचाने वाला है। वहीं, फ्रांस का कहना था कि अन्य देशों की कंपनियां उनके यहां या तो कॉर्पोरेट कर देती ही नहीं हैं या देती भी हैं तो बहुत ही कम। करों को लेकर असहमति से उत्तेजित ट्रंप ने वाईन को लेकर फ्रांस की आलोचना करने से गुरेज नहीं किया और धमकी दी की उनका देश फ्रेंच वाइन के आयात पर शुल्क लगाने पर विचार कर रहा है। अमेरिका वाइन की खपत और आयात करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है। वह जिन देशों से वाइन आयात करता है, उनमें फ्रांस भी शामिल है।

मध्य पूर्व को लेकर भी यूरोप और अमेरिका के मतभेद जगजाहिर हैं। ईरान संकट पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों चाह रहे हैं कि परमाणु करार टूटे नहीं। मैक्रों को जर्मनी और ब्रिटेन का भी समर्थन हासिल है। ये देश चाहते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच रिश्ते सुधरें जिससे इलाके में तनाव कम हो। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध से जापान और फ्रांस जैसे देश प्रभावित हुए हैं। फ्रांस चाहता है कि ईरान पर लगी अमेरिकी पाबंदी में ढील दी जाए जिससे तेल आयात का रास्ता साफ हो। इसके अलावा ब्रेग्जिट को लेकर ब्रिटेन और अमेरिका के संबंध खराब हो चुके हैं। ट्रंप की बयानबाजी ने

ब्रिटेन की आंतरिक राजनीति को प्रभावित किया है। ट्रंप ने ब्रिटेन से व्यापार को लेकर जहां बातचीत की बात कही, वहीं हाल में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि अगर अमेरिका ब्रिटेन के साथ व्यापार सौदा चाहता है तो उसे ब्रिटिश व्यापार पर से प्रतिबंध हटाना होगा। जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान जॉनसन ने स्वीकार किया कि अमेरिका में ब्रिटिश व्यवसायों के लिए बहुत बाधाएं हैं। ब्रिटेन की कंपनियों के लिए अमेरिकी बाजार में बड़े पैमाने पर अवसर की संभावनाएं देखते हुए जॉनसन अमेरिकी नीतियों में सुधार के हिमायती है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि रक्षा क्षेत्र में यूरोप में सबसे ज्यादा खर्च करने वाले ब्रिटेन ने अमेरिका समर्थित नाटो को हमेशा समर्थन दिया है। ब्रिटेन में कई अमेरिकी सैन्य अड्डे बने हुए हैं और दोनों देशों की सेना गृह युद्ध और आतंकवाद से प्रभावित कई देशों में सैनिक कार्रवाई में साझीदार भी रही है। इसके बाद भी आर्थिक हितों को लेकर दोनों देश आमने-सामने हैं। जाहिर है, न्यूयार्क और लंदन दुनिया के दो बड़े वित्तीय केंद्र भले हों लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन के बीच व्यापार में सहयोग का भविष्य इतना आसान नहीं दिखता।

यूरोप की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था इटली के चीन से रिश्ते भी अमेरिका को नागवार गुजर रहे हैं। इस साल मार्च में बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को लेकर इटली और चीन के बीच बंदरगाह, पुल और बड़े बिजली संयंत्र लगाने को लेकर हुए समझौते को भी ट्रंप के लिए झटका माना गया। रोम में आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री गिउसेप कोंटे और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मौजूदगी में दोनों देशों के अधिकारियों ने उनतीस अलग-अलग समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के साथ इटली बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट से जुड़ने वाला जी-7 समूह का पहला देश बन गया। चीन की इस परियोजना से अमेरिका ने दूरी बना रखी है। जहां तक जापान का सवाल है, अमेरिका और जापान के बीच व्यापारिक टकराव देखने को मिलता रहा है। येन और डॉलर की प्रतिद्वंद्विता दोनों देशों के आपसी संबंधों को चुनौतीपूर्ण बना रही है। इस साल ट्रंप ने जापान की यात्रा कर यह दावा किया था कि हम अमेरिका के निर्यात की बाधाएं और व्यापार असंतुलन को दूर करना चाहते हैं और हमारे संबंधों में पारस्परिकता सुनिश्चित करना चाहते हैं। ट्रंप ऊंची कर दरों की वजह से अमेरिका को होने वाले अरबों डालर के नुकसान के लिए जापान की आलोचना कर चुके हैं। इसी तरह जी-7 के एक और बड़े देश कनाडा के साथ भी अमेरिकी संबंध बद से बदतर देखे गए हैं। पिछले साल ट्रंप ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को 'बेईमान और कमजोर' तक कह दिया था।

बहरहाल दुनिया में अमेरिका की अर्थव्यवस्था का महत्त्व बरकरार है और उसके सहयोग के बिना साझा हितों की कल्पना नहीं की जा सकती। जाहिर है, ट्रंप को नियंत्रित और संतुलित रख ही जी-7 अपने उद्देश्यों में कामयाब हो सकता है लेकिन यह इतना आसान नहीं है। जी-7 के अन्य देश अमेरिका से उदार नीति की अपेक्षा करते हैं, जबकि ट्रंप 'अमेरिकी फर्स्ट' के लिए कृत संकल्पित हैं।

कथा नए स्कूल की

प्रेमपाल शर्मा

हाल में बुलंदशहर के अपने गांव के रास्ते में दोस्त ने बताया कि यहां खुर्जा और बुलंदशहर के बीच अल्पसंख्यकों के लिए कुछ नए स्कूल खुले हैं। योजना तो पिछली सरकार की थी लेकिन बन कर अब तैयार हुए हैं। देखने की उत्सुकता हुई और गाड़ी उधर मोड़ दी। जीटी रोड के मुख्य सड़क मार्ग से गांव की पतली-पतली गलियों के बीच लगभग एक किलोमीटर का रास्ता पार करके हम स्कूल पहुंचे। ऐसी भव्य इमारत! चमाचम! बीस कमरे, सुंदर-सा प्रवेश द्वार, खेल का मैदान, नए लगे पेड़। मन ऊर्जा से भर गया।

लेकिन उत्साह ठंडा होने में भी देर नहीं लगी। स्कूल छठी से लेकर बारहवीं तक का है लेकिन अभी सिर्फ दो कक्षाएं ही चलती हैं- नवीं और दसवीं की। पिछले वर्ष सिर्फ नवीं कक्षा ही चल रही थी। क्यों? यहां तो चारों तरफ बच्चों के लिए स्कूल है ही नहीं और इतनी अच्छे स्कूल में दाखिला क्यों नहीं? क्योंकि सरकार ने दो साल में अभी सिर्फ एक शिक्षक दिया है। उसे शिक्षक मानो, प्रिंसिपल मान लो या क्लर्क, वही सभी कुछ है। स्कूल की अकेली शिक्षिका अचानक हमारे पहुंचने से अचकचा गई। फर्श पर एक साथ दो कक्षाओं के बीच में उनकी कुर्सी थी। एक तरफ नवीं क्लास के बच्चे तो दूसरी तरफ दसवीं के। काश हार्वर्ड, कैंब्रिज के शिक्षाविद हमसे भी कुछ सीख पाते कि कैसे अकेले शिक्षक के बूते भारत में पूरा स्कूल चलाया जाता है।

जब ठीक-ठाक कक्षाएं हैं तो फर्श पर क्यों बैठे हैं? यह पूछने पर शिक्षिका ने व्यावहारिक बात बताई- 'मैं बीच में बैठ कर दोनों क्लासों को तो भी संभाल लेती हूं।' हमने पूछा- क्या सभी विषय पढ़ा लेती हैं? तो वे बोलीं-'क्या करें, मैं हूं अर्थशास्त्र की लेकिन बारी-बारी से सभी विषय पढ़ाने ही पड़ते हैं।' आप और शिक्षकों की मांग क्यों नहीं करते लिखित में? क्या डीएम और उच्च शिक्षा अधिकारियों को बताया? ऐसे प्रश्नों पर वे हकलाने लगीं कि कहीं कोई आफत न खड़ी हो जाए।

दुनिया मेरे आगे

लब्बोलुआब यह कि बार-बार कहने के बावजूद न शिक्षक नियुक्त हुए ,न क्लर्क और इसीलिए जो बच्चे दाखिला लेना भी चाहते हैं मसलन छठी, सातवीं क्लास में, वे भी नहीं आ पाते। इस बारे में गांव के प्रधान को भी सारी हकीकत पता है लेकिन वे दिल्ली रहते हैं यानी कि उनकी पत्नी गांव की प्रधान बनी हैं और पूरे परिवार के साथ में दिल्ली में रहती हैं। प्रधानी के दायित्व गांव में उनके छोटे भाई संभालते हैं, यानी कि भारतीय लोकतंत्र में खड़ाऊ प्रधानी। साल में असली प्रधान पत्नी तो मुश्किल से ही आती है, उनके पति कभी-कभी आते हैं जैसे पिछले बार एक सरकारी कार्यक्रम में पेड़ लगाने और फिर चुनाव के दौरान आए थे।

खुशी की बात यह थी कि बच्चों के चेहरे पर अद्भुत मुस्कुराहट थी। खिले-खिले ऊर्जा से भरे हुए। मानो घर के रोजाना के कामों से मुक्ति उन्हें स्कूल में रह कर ही मिलती हो। जुलाई के महीने में जरूर संख्या कुछ कम रहती है क्योंकि उन दिनों ये सब बच्चे खेतों में धान की रोपाई करने जैसे कामों में लगे रहते हैं। शिक्षिका समझदार लगती थीं क्योंकि उन्होंने कहा, इनके लिए पेट भरना ज्यादा जरूरी है बजाय स्कूल के और इसीलिए हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। वाकई लड़कियों की कॉपी में लेख को देख कर लगता था, काश इनके पंखों को और उड़ने का मौका मिलता!

कुछ लड़कियां अपने मां-बाप के साथ घर पर सिलाई और कढ़ाई-बुनाई का काम भी संभालती हैं। जाहिर है, बच्चे तो पढ़ना चाहते हैं लेकिन सरकार और समाज की ऐसी नीयत, व्यवस्था और विवशता के चलते दुनिया की सबसे नौजवान आबादी अभी भी सबसे निरक्षर आबादी है। काश, कभी डीएम या शिक्षा अधिकारी भी मुख्य शहर से सिर्फ तीन किलोमीटर पर स्थित इस स्कूल का दौरा कर पाते! शायद उन्हें अपने आला अफसरों और नेताओं की खुशामद से ही फुर्सत नहीं मिलती! काश प्रधान गांव में ही रहता और दिल्ली से लोकतंत्र नहीं चलाता! और यह भी कि यह स्कूल मुक्त सड़क के किनारे होता जहां बच्चों के आने-जाने की सुविधा रहती।

पता लगा कि स्कूल बनवाने के लिए तो सरकार चार करोड़ रुपए तक देती है लेकिन जमीन ग्राम सभा जिसकी कीमत दस लाख से अधिक नहीं होगी। और ग्राम सभा वहीं जमीन देती है जो किसी बियाबान में उसके अधिकार में है। इसीलिए न स्कूल जाने के रास्ते सही होते हैं, न आबादी और जरूरत के हिसाब से बनाए जाते हैं। और न फिर उनकी खैर खबर ली जाती है। चार करोड़ का ठेका तो तुरंत पूरा हो गया, अल्पसंख्यकों के लिए किए जाने वाले कामों की भी खानापूर्ति हो गई, सही शिक्षा का सपना न जाने कब पूरा होगा।

बदलते सुर

कश्मीर से धारा 370 को निष्क्रिय किए जाने के बाद से ही पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सरकार को आड़े हाथों लेते रहे हैं। लेकिन अब अचानक उनका कैसे हृदय परिवर्तन कैसे हो गया है? उनके स्वर एकदम बदल गए और वे सरकार के समर्थन कह रहे हैं कि मैं कई मामलों में सरकार से असहमत हूं पर कश्मीर में पाकिस्तान हिंसा भड़का रहा है और वह दुनियाभर में आतंकवाद का प्रमुख समर्थक बना हुआ है, कश्मीर का मसला भारत का आंतरिक मामला है इसमें किसी दूसरे देश के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। अगर राहुल अब हकीकत को मान रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने भले ही सरकार से अपनी वैचारिक भिन्नता बताई हो, किंतु देश के साथ उन्होंने सरकार के साथ खड़े होकर खुद, पार्टी, जनहित और देशहित में दिल से जो कहा वह सराहनीय है। इस तरह कांग्रेस ने एक बेहतर संदेश विपक्षियों को दिया है कि आंतरिक मतभेद चाहे कितने भी हों लेकिन राष्ट्रहित में हमें हमेशा सरकार के साथ एकजुट होकर खड़े होना चाहिए।

● *शकुंतला महेश नेनावा, इंदौर*

बौखलाया पाक

जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को हटाए जाने के बाद से पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया हुआ है। इस बौखलाहट में वह दुनिया के दूसरे देशों के आगे इस मामले में दखल देने की फरियाद करता घूम रहा है। लेकिन सारी दुनिया पाकिस्तान की मंशा को जानती है, इसलिए किसी भी देश ने उसे कोई तवज्जो नहीं दी और इस मामले में इसका साथ देने से भी इंकार कर दिया, यहां तक कि मुसलिम देशों ने भी इस मुद्दे पर उसका साथ देने से साफ मना कर दिया। इस बौखलाहट में आकर पाकिस्तान ने परमाणु युद्ध की धमकी भी दे डाली। यह उसकी सबसे बड़ी नासमझी है। वह शायद भूल चुका है कि भारत के साथ हर युद्ध में उसकी करारी हार हुई है। जंग हमेशा नुकसानदायी होती है, पाकिस्तान के सत्ताधारी और कट्टरपंथी इस बात को क्यों नहीं समझते। बल्कि अगर पाकिस्तान को खुद एक बेहतर राष्ट्र बनना है तो उसे अपने यहां पल रहे आतंकी संगठनों पर नकेल कसनी चाहिए। पाक को यह बात याद रखनी चाहिए कि परमाणु बमों का असर आज तक नागासाकी और हिरोशिमा के लोग भुगत रहे है। परमाणु युद्ध किसी मसले का हल नहीं हो सकता।

● *राजेश कुमार चौहान, जलंधर*

सदुपयोग हो पैसे का

रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को पौने दो लाख करोड़ रुपए हस्तांतरित करने का फैसला किया है। देश का पैसा, देश को मिले और जनहित में अगर इसका सदुपयोग होता है तो यह निर्णय बहुत ही सराहनीय व स्वागत योग्य है। लेकिन अब तक जो भी देखने और सुनने में आया है कि केंद्र सरकार देश व जनहित में जितनी भी अच्छी योजनाएं बनाती है, पैसा देती है, उस पैसे का उपयोग कम, दुरुपयोग ज्यादा होता है। चाहे वह बैंकों से कर्ज लेकर भाग जाने का मामला हो या इन योजनाओं में भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी का मामला हो। केंद्र सरकार को अब व्यापक व समग्र रूप से यह प्रयास करना चाहिए कि पाई-पाई पैसे का सदुपयोग देश व जनहित में हो, ताकि सरकार के इस फैसले की आलोचना करने वालों का मुंह बंद हो सके।

● *हेमा हरि उपाध्याय, खाचरोद (उज्जैन)*

अनूठी पहल

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ने एक अनुकरणीय पहल करते हुए टीबी पीड़ित एक बच्ची के इलाज का पूरा खर्चा उठाने का संकल्प लिया और सबसे अच्छी बात यह

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

रही कि तत्काल बाद राजभवन के कई अधिकारियों ने इसी तरीके की पहल करते हुए टीबी पीड़ित बच्चों को इलाज के लिए गोद लिया। काश, आज भारत में सभी साधन संपन्न लोग अगर इसी तरीके से पहल करते हुए शिक्षा से वंचित या इलाज से वंचित गरीब बेसहारा बच्चों को गोद लेकर के उनकी परवरिश की जिम्मेदारी उठा लें तो हम एक सशक्त और मजबूत समाज की स्थापना कर सकेंगे।

● *रमेश माहेश्वरी, सुल्तानपुर*

कामयाबी का शिखर

कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जो कामयाबी के पीछे नहीं बल्कि कामयाबी उनके पीछे भागती है और ऐसे में वे आसमान में इतनी सीढ़ियां लगा लेती हैं कि उनके साथ चलने वाले काफी पीछे छूट जाते हैं। पीवी सिंधू, हिमा दास, दुती चंद से लेकर मैरीकॉम, सानिया मिर्जा और गीता फोगाट तक आसमान में चमकने वाले कुछ सितारे ऐसे ही हैं जो सफलता के उस मुकाम पर हैं जहां पहुंचना मुश्किल तो नहीं पर फिलहाल भारतीय महिला खिलाड़ियों के लिए आसान भी नहीं है। खेलों का हम सभी से नाता रहा है। देश में खेलों को प्रोत्साहन मिलने के साथ इन दिनों बड़ी संख्या में महिलाएं इसमें करियर बना रही हैं। बात चाहे क्रिकेट या हॉकी की हो या तैराकी और फुटबॉल की हर क्षेत्र में प्रतिभाओं की भरमार है। लेकिन प्रतिभा तभी निखरती है जब उसे तराशा जाए। आज महिलाएं आत्मनिर्भर, स्वनिर्मित और आत्मविश्वासी हैं जिन्होंने पुरुष प्रधान चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में भी अपनी योग्यता प्रदर्शित की है। वे केवल शिक्षिका, नर्स, डाक्टर न बन कर इंजीनियरिंग, वैमानिकी, सेना, पत्रकारिता जैसे नए क्षेत्रों को अपना रही हैं। राजनीति के क्षेत्रों में महिलाओं ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं।

बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध और अब इक्कीसवीं सदी के प्रारंभ में बराबरी व्यवहार वाले जोड़े बन रहे हैं। नौकरी वाली नारी के साथ पुरुष की मानसिकता में भी बदलाव आया है। पहले नौकरी वाली औरत के पति को औरत की कमाई खाने वाला कह कर चिढ़ाया जाता था। लेकिन आज यह सोच बदल चुकी है। स्त्री अब अत्मनिर्भर है। महिलाओं के संबंध मे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि यदि आपको देश का विकास करना है तो महिलाओं का उत्थान करना होगा। महिलाओं का विकास होने पर समाज व देश का विकास स्वतः हो जाएगा।

● *अमन सिंह, बरेली*

epaper.jansatta.com